बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 184 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 22 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाई कोर्ट में 6 नए जजों ने ली शपथ, कुल संख्या 41 हुई

नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट में 21 जुलाई को 6 नए जजों ने पद की शपथ ली. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है. इन नए जजों का स्थानांतरण विभिन्न हाई कोर्ट्स से किया गया है,

जिनमें बॉम्बे, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट शामिल हैं. इस घटनाक्रम को न्यायपालिका में मजबूती और विविध अनुभवों के समावेश के रूप में देखा जा रहा है.

शपथ लेने वाले नए जजों के नाम

जिन जजों ने आज शपथ ली उनके नाम हैं, न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और यमूर्ति ओ. पी. शुक्ला. इन सभी जजों ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली. जस्टिस वी. कामेश्वर राव पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में कार्यरत थे और अब वे अपने मूल दिल्ली हाई कोर्ट में लौटे हैं. वहीं, जस्टिस नितिन सांबरे बॉम्बे हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर आए हैं.

कहां से कौन जज ट्रांसफर होकर आए?

जस्टिस वी. कामेश्वर राव- कर्नाटक हाई कोर्ट से, जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे- बॉम्बे हाई कोर्ट से, जस्टिस विवेक चौधरी- इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जस्टिस अरुण मोंगा- राजस्थान हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जस्टिस ओ. पी. शुक्ला.

वरिष्ठतम जज के प्रमोशन से कॉलेजियम में बदलाव

दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस विभु बाखरू को 16 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उनके स्थानांतरण के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के तीन सदस्यीय कॉलेजियम में भी पुनर्गठन किया गया है, जिससे न्यायिक कार्यों की दिशा और प्राथमिकताएं प्रभावित होंगी. यह नियुक्ति और पुनर्गठन आने वाले समय में दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा.

हर हद पार कर रही ईडी, वकीलों को नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; जल्द ही दिशा-निर्देश बनाने को कहा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से वकीलों को तलब करने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की कैर्यशैली को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी वकीलों को समन भेजकर हर हद पार कर रही है, जो कानून के पेशे की स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। मामले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। यह सुनवाई उन मामलों से जुड़ी है जिनमें वकीलों को सिर्फ अपने मुवक्किलों को कानूनी सलाह देने पर ईडी ने नोटिस भेजे हैं। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वकील और मुवक्किल के बीच की बातचीत एक गोपनीय संवाद होती है। ऐसे में वकीलों को नोटिस भेजना सरासर गलत है। एजेंसी हद से बाहर जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने। बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान ये मामला भी सामने आया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार जैसे बड़े नामों को भी ईडी की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं, जिससे वकालत के पेशे पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही मेहता ने बताया कि जांच एजेंसी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को नोटिस नहीं भेजे जाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो वकील सिर्फ कानूनी सलाह दे रहे हैं, उन्हें समन नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामलों में संस्थानों की छवि खराब करने की कोशिश भी की जाती है। गौरतलब है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वकीलों की स्वतंत्रता और उनके पेशे के अधिकारों को बचाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुवक्किल और वकील के बीच की बातचीत को छेड़ना संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ है।

नई दिल्ली (इंद्रजीत सिंह) राजीव भवन, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की पूर्ण तिथि पर पुष्प अर्पित करते वरिष्ठ पत्रकार ,विजय शंकर चतुर्वेदी ,संपादक, राष्ट्र टाइम्स पत्रिका । छाया- साहिल गौड़

बीजेपी सांसद तरविंदर सिंह मारवाह का बड़ा बयान, पाकिस्तानी एजेंट कांवड़ यात्रा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं

नई दिल्ली । दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एजेंट इस पवित्र यात्रा में घुसपैठ करके उपद्रव कर रहे हैं और यात्रा की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे है. मारवाह ने कहा कि हाल ही में दो-तीन जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं, वो साजिश के तहत की गई और इसके पीछे पाकिस्तान के स्लीपर सेल सक्रिय हैं. ऐसे हालात को देखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि अब अगले साल से सभी कांवड़ियों को पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिन पर मंदिर की मोहर होगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल असली श्रद्धालु ही यात्रा में शामिल हों और उपद्रवी तत्वों की पहचान पहले से हो सके. विधायक मारवाह ने चेतावनी भी दी कि जो कोई भी इस धार्मिक यात्रा में शांति भंग करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. इस बीच दिल्ली में हिंदू-सिख एकता की सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं. सिख समाज की ओर से कांवड़ियों के स्वागत में फूलों की वर्षा की गई और उनके लिए विशेष विश्राम स्थल बनाए गए, जहां उन्हें ठंडा शरबत, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा दी गई. इस सेवा कार्य का आयोजन केंद्रीय गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिन्होंने इस यात्रा को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर सम्मानित किया. विधायक मारवाह ने कहा कि यह सेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि भारत की सांप्रदायिक एकता और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण है. उन्होंने बताया कि गुरु सिंह सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, नड्डा बोले- सरकार तैयार

नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले, बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। दूसरी ओर, सरकार जीएसटी, खनन, खेल आदि से संबंधित विभिन्न विधेयकों पर चर्चा करने वाली है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के विवरण पर चर्चा की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। जवाब में, भाजपा के जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। खड़गे ने कहा कि मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। आज तक, आतंकवादियों को पकड़ा या बेअसर नहीं किया गया है। सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। उन्होंने पूछा कि सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ है। जम्मू-कश्मीर के एलजी ने बयान दिया था कि खुफिया विफलता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 24 बार दावा किया है कि संघर्ष विराम केवल उनके हस्तक्षेप के कारण हुआ। खड़गे को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सदन में ऑपरेशन सिन्दूर पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को करारा जवाब दिया, उससे हमने दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह सत्र ऑपरेशन सिंदूर का उत्सव है और हम इसे मनाने जा रहे हैं। जो लोग अपने देश और उसकी सेना पर गर्व करते हैं, वे ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न जरूर मनाएंगे और हम इसी भावना के साथ संसद में प्रवेश कर रहे हैं।

लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उपराष्ट्रपति बोले- राजनीतिक तनाव घटाने की जरूरत

नई दिल्ली । राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि एक फलता-फूलता लोकतंत्र निरंतर कटुता के हालात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक पार्टियों से एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर निजी हमले न करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत और चर्चा ही संघर्ष के बिना आगे बढ़ने का रास्ता हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से तनाव घटाने और विकास की राजनीति करने की अपील की। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। उपराष्ट्रपति का यह बयान इस मायने में भी अहम है क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आदि जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है और सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक फलता-फूलता लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजनीतिक तनाव घटना चाहिए। टकराव राजनीति का सार नहीं है। राजनीतिक दल अलग-अलग तरीकों से समान लक्ष्य पाने के प्रयास कर सकती हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्र के हितों का विरोध नहीं करता। राज्यसभा सभापति ने सभी राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा या व्यक्तिगत हमलों से बचने का आग्रह किया।

दिल्लीवाले हो जाएं खुश : यमुनापार में नए रूट पर चलेंगी देवी बसें, मेट्रो यात्रियों को जोड़ेंगी

नई दिल्ली ।राजधानी की सड़कों पर चल रहीं नई इंवी कनेक्टर (देवी) बसों को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुनापार में नए बस रूट तैयार किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दरअसल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का जोर है। कम लंबाई वाली 9 मीटर की इन बसों के लिए सरकार राजधानी में 145 नए रूट शुरू करने की तैयारी में है। इन रूटों को खास तौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मेट्रो स्टेशनों से बेहतर तरीके से जोड़ने को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देवी बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और क्लस्टर बसों के 12 मीटर लंबी बसों के रूट पर दौड़ रही हैं जहां इनकी प्रभावशीलता सीमित नजर आई है। बड़ी बसों के मुकाबले छोटी देवी बसों में सवारियां कम हैं। इसकी वजह यह है कि ये बसें उन इलाकों में नहीं चल पा रही हैं जहां इनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। ऐसे में आईआईटी दिल्ली की मदद से 145 नए रूटों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सरकार सबसे पहले यमुना विहार से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में इन रूटों को लागू किया जाएगा। इन रूटों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे कॉलोनियों और मेट्रो स्टेशनों के बीच सुगम कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। विभाग सिर्फ बसें नहीं बल्कि खास डिजिटल बस स्टॉप भी विकसित कर रहा है। इन स्टॉप पर छोटी डिजिटल स्क्रीन लगी होंगी जो रूट नंबर, बस की लोकेशन, आगमन व प्रस्थान समय जैसी जानकारियां दिखाएंगी। इस परियोजना को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के सहयोग से अमलीजामा पहनाया जाएगा।

'सीटियों' वाला भारतीय गांव 'कोंगथोंग'

ग्रामीणों को अपने निवासियों के नाम के रूप में जिंग्रवाई इओबेई धुनों की अनूठी परंपरा को जीवित रखने की चिंता है। वे स्कूल को उच्च कक्षाओं में अपग्रेड करने और स्कूल में 'सीटी भाषा' पढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैनरी द्वीप में सिल्बो गोमेरो सीटी भाषा 22,000 चिकित्सकों के साथ और तुर्की पक्षी भाषा 10,000 चिकित्सकों के साथ स्कूल में पढ़ाई जाती है और दोनों को क्रमशः 2013 और 2017 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि केवल 700 चिकित्सकों के साथ जिंग्रवाई इओबेई को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है जिससे इसके संरक्षण के लिए चिंताएं पैदा होती हैं।

जहां एक ओर मराठी, तमिल, पंजाबी व अन्य भाषाओं को लेकर विवादों के सिलसिले जारी हैं, वहां भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक गांव 'कोंगथोंग' अपनी सीटियों की भाषा में ही बात करने में सुख पाता है। कोंगथोंग, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता के लिए भारत की प्रविष्टि है और यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए दावेदार है। कोंगथोंग एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने मनोरम दृश्यों और निवासियों की अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग सीटी वाली भाषा 'जिंग्रवाई इओबेई' का उपयोग करते हैं। अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित कई देशों के पर्यटक और भाषा शोधकर्ता यहां आते हैं। गांव के प्रत्येक मूल निवासी का एक अनूठा नाम है जो एक सीटी वाली लोरी है और ग्रामीण एक-दूसरे को लोरी बजाकर बुलाते हैं। कोंगथोंग अर्थात 'जिंग्रवाई इओबेई' सीटी वाली लोरी के नाम से जाना जाता है। जहां प्रत्येक मूल निवासी के पास अपने लिए एक अद्वितीय सीटी वाली लोरी का नाम है और वे एक दूसरे को इस लोरी को सीटी बजाकर बुलाते हैं। भूगोल - कोंगथोंग गांव पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक शांत और मनोरम पहाड़ी गांव है। गांव की आबादी लगभग 500 से 700 लोगों की है। जिंग्रवाई इओबेई (सीटी भाषा) - कोंगथोंग के लोग खासी जनजाति से हैं जो खासी भाषा बोलते हैं जो एक बोलचाल की भाषा है। हालांकि कोंगथोंग में गांव के प्रत्येक सदस्य के नाम के रूप में अनोखी सीटी की धुन रखने की विशिष्ट परंपरा है। इसे 'जिंग्रवाई इओबेई' अर्थात 'मूल पूर्वज' के सम्मान में गाया जाने वाला राग माना जाता है। प्रत्येक नवजात शिशु को मां द्वारा एक अनोखे नाम के रूप में दिया जाता है जो उस व्यक्ति की स्थायी पहचान बन जाता है। यह नाम एक शब्द नहीं है बल्कि एक सीटी के रूप में एक अनोखा कॉल नाम या कॉलर ट्यून है, यानी 'कॉल' करने वाला एक धुन गुनगुनाता है जो एक अनोखा 'नाम' है जिसे केवल ग्रामीणों द्वारा ही समझा जा सकता है।' शिशुओं का यह नामकरण एक मातृसत्तात्मक परंपरा है जिसमें मां बार-बार सीटी के रूप में विशिष्ट संगीतमय धुन गुनगुनाती है जिसके बढ़ते बच्चे धीरे-धीरे आदी हो जाते हैं। यह अनोखी सीटी की धुन या 'जिंग्रवाई इओबेई लोरी' व्यक्ति का अनूठा नाम और स्थायी पहचान बन जाती है सभी ग्रामीण एक-दूसरे को उनके लिए निर्धारित विशिष्ट कॉलर ट्यून से बुलाते हैं। प्रत्येक जिंग्रवाई इओबेई या व्यक्ति के विशिष्ट नाम के दो रूप होते हैं, छोटा और लंबा। इस परंपरा पर शोध करने वाले शोधकर्ता डॉ. पियाशी दत्ता के अनुसार, प्रत्येक कबीले का एक मूल पूर्वज होता है। हर बार जब किसी बच्चे के लिए धुन बनाई जाती है तो उस पूर्वज का सम्मान किया जाता है। 'जिंग्रवाई इओबेई' एक राग (जिंग्रवाई) है जो मूल पूर्वज (इओबेई) के सम्मान में गाया जाता है। इस परंपरा की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथाएँ हैं जो इस बात पर केंद्रित है कि 'कैसे एक आदमी कुछ गुंडों से जूझते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्तों के नाम सीटी बजाकर पुकारे ताकि वे आकर उसे बचाएं और गुंडों को इसकी ज़रा भी भनक न लगे'। संवाद करने के इस अनोखे तरीके ने दुनियाभर के पर्यटकों के साथ-साथ भाषा अनुसंधान विद्वानों को भी आकर्षित किया है। इस गांव में 8वीं कक्षा तक का एक मिडिल स्कूल है। यह गांव सोहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ग्रामीण अपनी फसल बेचने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरकर बाजारों तक लंबी यात्राएं करते हैं, जहां वे पूरे गांव के लिए हफ्ते भर की जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं। परिवहन - कोंगथोंग, शिलांग से लगभग 65 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है जो 2017 तक ऐसे अन्य गांवों की तरह ही दुरस्थ बना हुआ है लेकिन हाल ही में एक मोटर योग्य सड़क से जुड़ा है। चेरापूंजी (दक्षिण-पश्चिम), खतरशनोंग (उत्तर), पिनुरस्ला (दक्षिण-पूर्व) और डावकी (दक्षिण-पूर्व, बांग्लादेश-भारत सीमा पर एक हाट और आव्रजन चौकी) पास के बड़े शहर हैं। ये सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। शिलांग हवाई अड्डा (65 किमी उत्तर पूर्व) और सेला हवाई अड्डा (75 किमी दक्षिण पूर्व) निकटतम हवाई अड्डे हैं। मैदीपाथर रेलवे स्टेशन (272 किमी उत्तर पश्चिम) निकटतम रेलवे स्टेशन है। कोई भी इस गांव कोंगथोंग की यात्रा कर सकता है जिसका एक रास्ता घाटियों और दूसरी तरफ चट्टानों वाले पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है और यह एक बेहद सुखद व मनोहारी अनुभव है। यह गांव मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें से कुछ पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले सबसे नम मार्ग में से है (पहले चेरापूंजी सबसे अधिक नम हुआ करता था, अब पास के मावसिनराम ने इसे सबसे नम बना लिया है)। इस क्षेत्र में जीवित जड़ पुल, जलप्रपात और भौगोलिक संरचनाएं हैं जैसे 'लिंगकिरेंग म्योर' जो एक प्राकृतिक पत्थर का पुल है जो दो चट्टानों को सोहरा नदी से जोड़ता है जो इसके बीच फटे नीचे बहती है। पर्यटक स्थानीय 'ग्रामीण-पर्यटन' के आतिथ्य का आनंद लेते हैं। ग्रामीणों को अपने निवासियों के नाम के रूप में जिंग्रवाई इओबेई धुनों की अनूठी परंपरा को जीवित रखने की चिंता है। वे स्कूल को उच्च कक्षाओं में अपग्रेड करने और स्कूल में 'सीटी भाषा' पढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कैनरी द्वीप में सिल्बो गोमेरो सीटी भाषा 22,000 चिकित्सकों के साथ और तुर्की पक्षी भाषा 10,000 चिकित्सकों के साथ स्कूल में पढ़ाई जाती है और दोनों को क्रमशः 2013 और 2017 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि केवल 700 चिकित्सकों के साथ जिंग्रवाई इओबेई को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है जिससे इसके संरक्षण के लिए चिंताएं पैदा होती हैं।

संसद का 'सावन' सत्र

संसद का सावन (वर्षाकालीन सत्र) से शुरू हो गया। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, ऐसी अपेक्षा देशवासियों को करनी चाहिए। फिर भी पुराना इतिहास बताता है कि संसद हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप के शोर-शराबे में डूब जाती है। हमारी संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में संसद के प्रति जनता का विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि संसद के 'सत्र-दर-सत्र' जिस तरह खानापूर्ती में गुजर जाते हैं उससे देश की जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता जिसका असर पूरे लोकतन्त्र पर पड़ता है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि संसद की जनता के प्रति जवाबदेही किसी भी सूरत में कम न हो। बेशक संसदीय प्रणाली स्थापित नियम-कायदों से ही चलती है जिसका ध्यान सरकार व विपक्ष दोनों को रखना पड़ता है। अगर जनता के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जवाबदेही कम होती है तो लोकतन्त्र अन्दर से कमजोर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि संसद में बैठने वाले सदस्यों को आम जनता ही चुनकर भेजती है। जो भी और जिस भी पार्टी के सदस्य संसद के सदस्य बनते हैं उन सभी की आवाज देश की 140 करोड़ जनता की होती है। इसीलिए संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान निर्माताओं ने सत्ता पक्ष पर डाली, क्योंकि विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों का चुनाव भी आम जनता ही करती है। अतः संसद केवल वाद-विवाद का अखाड़ा नहीं होती, बल्कि यह देश हित व जनहित में फैसले करने वाली संस्था होती है। इसीलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की खास जिम्मेदारी होती है कि संसद में बिना शोरगुल के जनता व देश के मुद्दे उठाये जायें। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, जो कि उसका दायित्व है। सत्ता पक्ष का दायित्व भी संसदीय प्रणाली में इस प्रकार नियत है कि वह विपक्ष द्वारा उठाये गये हर जायज मुद्दे का जवाब दे। इस मामले में अगर राज्यसभा व लोकसभा दोनों में अहम की कोई लड़ाई छिड़ती है तो उसे हम अनावश्यक भी नहीं कह सकते क्योंकि स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार संसद पर पहला अधिकार विपक्ष का ही होता है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के पाले में बैठने वाले सदस्य प्रायः अपेक्षाकृत रूप से आम जनता के सम्पर्क में ज्यादा रहते हैं। अतः उन्हें जन समस्याओं की जानकारी सीधे आम जनता ही देती है। यही कारण है कि विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी के किसी एक सदस्य को विपक्ष के नेता (लीडर ऑफ अपोजीशन) का रुतबा 'अता' किया जाता है और उसे किसी कैबिनेट मन्त्री के बराबर मिलने वाली सुविधाओं से नवाजा जाता है। संसद को चलाने में दोनों सदनों के अध्यक्षों या सभापतियों को अधिकृत किया जाता है। अध्यक्ष की कुर्सी की तुलना भारतीय संस्कृति के महान न्यायविद् सम्राट विक्रमादित्य के आसन से की जाती है क्योंकि वह सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक होते हैं और उनका चुनाव सभी सदस्यों द्वारा प्रायः सर्वसम्मति से किया जाता है। उनका हर आदेश न्याय की कसौटी पर खरा उतरे, इसकी व्यवस्था हमारे संसदीय संविधान में ही पुख्ता तौर से की गई है।

उनका हर फैसला पूरी तरह निष्पक्ष व पक्षपात से परे होना चाहिए। इस बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की है वह पूरी तरह संसद को सरकारी दबाव से मुक्त रखने की है। लोकसभा के अध्यक्ष सरकार का अंग नहीं होते। संसद परिसर में उनका ही आदेश चलता है। बेशक वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त सरकार के राजनैतिक दल के टिकट पर ही चुनाव जीतते हों मगर आसन पर बैठने के बाद वह 'अराजनैतिक' हो जाते हैं। पहले यह परम्परा थी कि जो भी सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता था वह अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देता था। मगर स्व. इन्दिरा गांधी के शासनकाल में इस प्रथा को छोड़ दिया गया जो अभी तक जारी है। सदन के सभापति या अध्यक्ष इस हकीकत से वाकिफ रहते हैं कि संसद में विपक्ष के सवालों का उत्तर देने के लिए सरकार बाध्य होती है। इसके बावजूद संसद के हर सत्र में शोर-शराबा व नारेबाजी आम बात हो गई है। यह स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर संसद न चलने की जिम्मेदारी डालते हुए नजर आते हैं। जाहिर है कि लोकतन्त्र में जनता की नजरों में चढ़ने के लिए विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होना चाहेगा जिसे निरुत्तर करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को उठानी होगी। मगर इसके जवाब में संसद में गतिरोध का उत्पन्न होना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक संसदीय कार्यमन्त्री की नियुक्ति भी होती है और उसी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष व सत्ता पक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करे जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके। आज से चालू सावन सत्र में विपक्ष ने घोषणा कर दी है कि वह पहलगाम घटना से लेकर बिहार में हो रहे मतदाता सूची की पुनरीक्षण का मामला उठायेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों को केन्द्र में लेगा। विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति खासकर चीन, पाकिस्तान व फलस्तीन के बारे में उसके रुख पर संसद में चर्चा कराना चाहेगा। विपक्ष द्वारा उठाये जाने वाले हर मुद्दे का जवाब सरकारी पक्ष से मिले, इसकी व्यवस्था अध्यक्ष व सभापति ही करते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले सत्रों में जब भी अपना मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आया उसकी अनुमति आसन की तरफ से नहीं दी गई और इसी बात पर संसद में शोर-शराबा व गतिरोध तक पैदा हुआ। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसद की नियमावली में जो उपाय हैं वे भी बहुआयामी हैं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि संसद चलनी चाहिए। मौजूदा सत्र में सरकार आठ नये विधेयक लेकर आ रही है और सात पुराने विधेयकों को पारित कराने जा रही है। विपक्ष को इन सरकारी विधेयकों पर भी गौर करना होगा जिससे संसद ठीक-ठाक तरीके से चल सके। लोकतन्त्र को जीवन्त बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे का सम्मान करें।

'कांवड़ ज़रूर लाइये और ज्ञान को दूर भगाइये'

सावन चल रहा है। पुराना जमाने में कवि लिखते थे और लोग गाते थे, सावन के झूले पड़े। तुम चले आओ, तुम चले आओ। आज के जमाने का कोई आधुनिक कवि होगा तो वह लिखेगा, सावन की कांवड़ चली। तुम कहीं ना जाओ, तुम बाहर ना जाओ। यह बात पूरे देश के लिए भले ही ठीक ना हो, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए तो ठीक ही है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं और आपके घर के आसपास से, काम पर आने जाने के रास्ते से, कहीं से भी, कांवड़िये नहीं गुजर रहे हैं तो आप भाग्यवान हैं। कम से कम सावन के पहले पंद्रह दिन तो भाग्यवान हैं ही। बारिश के मौसम में कष्ट तो होता ही है पर आपके कष्ट उन लोगों के मुकाबले कम है जिनके घर के पास से, काम पर आने जाने के रास्ते से कांवड़िये गुजरते हैं। देखो, बारिश के मौसम में बाढ़ आना, सड़कों पर पानी भर जाना तो पूरे विश्व में होता है पर हमारे यहां एक बार सड़क पर पानी भर जाये तो जल्दी नहीं निकलता है, पूरे सीजन भरा रहता है। सड़क और पानी में इतना प्यार है कि एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जनम जनम का साथ है हमारा तुम्हारा टाइप। जब अलग होते हैं तो वादा करते हैं, फिर मिलेंगे, अगले साल फिर मिलेंगे और इसी तरह हर साल प्यार से लम्बे समय तक एक साथ रहेंगे। लेकिन बारिश के मौसम में ये जो पुल ढह जाना, सड़कें बह जाना वाली बात है ना, यह हमारे देश की ही खासियत है। जो पुल जितना नया हो उसके गिरने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। पुराने पुल कम गिरते हैं। अभी गुजरात में चालीस साल पहले बना पुल गिरा तो चैन की सांस ली। नहीं तो हर समय यही समाचार आता है कि दो साल पहले बना पुल गिर गया, दो महीने पहले बना पुल गिर गया। नई तकनीक अपनाते हैं, ड्रोन से निरीक्षण करते हैं, पैसा भी खूब लगाते है और कमीशन भी भरपूर खाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों टिकाऊ पुल नहीं बना पाते हैं। यही बात सड़क के बारे में है। सड़क उतने बजट में बन रही है जितने में, अगर बनाना चाहें तो सोने की सड़क बन जाए। सड़क बनाने की कीमत बढ़ते बढ़ते एक हजार करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर तक पहुंच गई है। और फिर भी सड़क सोने चांदी की नहीं, वही तारकोल, रोड़ी और सीमेंट की बन रही है। पर बन इतनी नाजुक रही है कि जैसे सोने की बनी हो। सच में इतनी नाजुक कि पहली बारिश में ही बह जाती है। और लोगबाग उन पर गाड़ियां चला कर गड्ढे कर देते हैं। गलती लोगों की ही है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सड़कें गाड़ियां चलाने के लिए नहीं, सिर्फ आंकड़ों के लिए बनी हैं। बात हम कांवड़ की कर रहे थे और बात करने लगे पुल और सड़कों की। इसी को मतिभ्रम कहते हैं। यह मुझ में ही नहीं, पूरे देश में फैला हुआ है और बहुतायत में फैला हुआ है। अब एक मास्साब, मतलब वही स्कूल के टीचर, उन्हें मतिभ्रम हो गया। स्कूल में बच्चों को कविता सुनाने लगे, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना; मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना।

सम्पादकीय...

बढ़ती बेरोज़गारी एक विकट समस्या

पिछले दिनों खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में 2 हजार पदों के लिए 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसी तरह एक बार ऐसी भी खबर आई थी कि आईआईटी से पास हुए 38 फीसदी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी कभी कोई सरकारी पद पर भर्ती खुलती है तो कुछ हजार पदों के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं, फिर वो पद छोटा हो या बड़ा, उस पद की योग्यता से अधिक योग्य आवेदक अपना आवेदन देते हैं। बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की या देश में किसी अन्य राज्य की, जब भी एक पद पर उम्मीद से ज्यादा आवेदन आते हैं तो स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। आज के दौर में अगर 'मैनस्ट्रीम मीडिया' किन्हीं कारणों से ऐसे सवालों को जनता तक नहीं पहुंचाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनता तक वह सवाल पहुंच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू देखें जा सकते हैं जो बेरोजगारी की भयावय समस्या से जूझते युवाओं की हताशा दर्शाते हैं। जब ये युवा रोजगार की मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो इनके राज्यों की सरकारें पुलिस से इन पर डंडे बरसाती हैं, अगर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की भी उम्मीद नहीं होगी तो हार कर उन्हें निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा और निजी क्षेत्र की मनमानी का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बहुत तेजी से घटती जा रही हैं। इससे और हताशा फैल रही है। नौकरी नहीं मिलती तो युवाओं की शादी नहीं होती और उनकी उम्र बढ़ती जाती है। समाज शास्त्रीय शोधकर्ताओं को इस विषय पर शोध करना चाहिए कि इन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की इस हताशा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को देखते हुए शहरों में अनौपचारिक रोजगार की मात्रा को क्रमशः घटा कर औपचारिक रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देश की सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। एक शोध के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र में 50फीसदी, व्यापार, होटल व अन्य सेवाओं में 47फीसदी, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में 39फीसदी और खनन क्षेत्र में 23फीसदी बेरोजगारी फैल चुकी है। चिंता की बात यह है कि ये वो क्षेत्र हैं जो देश को सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। इसलिए उपरोक्त आंकड़ों का प्रभाव भयावह है। जिस तीव्र गति से ये क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं उससे तो और भी तेजी से बेरोजगारी बढ़ने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ न कर पाने की हालत में लाखों मजदूर व अन्य लोग जिस तरह लॉकडाउन शुरू होते ही पैदल ही अपने गांवों की ओर चल पड़े उससे इस स्थिति की भयावयता का पता चलता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के देशों में अनौपचारिक रोजगार के मामले में भारत सबसे ऊपर है। जिसका मतलब हुआ कि हमारे देश में करोड़ों मजदूर कम मजदूरी पर, बेहद मुश्किल हालातों में काम करने पर मजबूर हैं, जहां इन्हें अपने बुनियादी हक भी प्राप्त नहीं हैं। इन्हें नौकरी देने वाले जब चाहे रखें, जब चाहे निकाल दें, क्योंकि इनका ट्रेड यूनियनों में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत में 53.5 करोड़ मजदूरों में से 39.8 करोड़ मजदूर अत्यंत दयनीय अवस्था में काम करते हैं। जिनकी दैनिक आमदनी 200 रुपये से भी कम होती है। इसलिए मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, शहरों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं? क्योंकि पिछले 7 वर्षों में बेरोजगारी का फीसदी लगातार बढ़ता गया है। दूसरा, शहरी मजदूरों की आमदनी कैसे बढ़ाएं जिससे उन्हें अमानवीय स्थित से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए तीन काम करने होंगे। भारत में शहरीकरण का विस्तार देखते हुए शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय करके नीतियां बनानी होंगी। इससे यह लाभ भी होगा कि शहरीकरण से जो बेतरतीब विकास और गंदी बस्तियों का सृजन होता है उसको रोका जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय शासन को अधिक संसाधन देने होंगे। दूसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन वाली विकासात्मक नीतियां लागू करनी होंगी। तीसरा, शहरी मूलभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुधरे। चौथा, देखा यह गया है कि विकास के लिए आवंटित धन का लाभ शहरी मजदूरों तक कभी नहीं पहुंच पाता और ऊपर के लोगों में अटक कर रह जाता है। इसलिए नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर खरीदी जा रही भारी मशीनों की जगह अगर मानव श्रम आधारित शहरीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा तो शहरों में रोजगार बढ़ेगा। पांचवां, शहरी रोजगार योजनाओं को स्वास्थ्य और सफाई जैसे क्षेत्र में तेजी से विकास करके बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आज यह हालत नहीं है कि वो प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सके, अगर होती तो वे गांव छोड़कर शहर नहीं गए होते। मौजूदा हालात में यह सोचना कि पढ़े-लिखे युवाओं के लिए एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिससे इनको भी रोजगार मिल जाए। पर ऐसा करने से करोड़ों बेरोजगारों का एक छोटा सा अंश ही संभल पाएगा, जबकि बेरोजगारों में ज्यादा तादाद उन नौजवानों की है जो आज देश में बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं। उनका आक्रोश इतना बढ़ चुका है और सरकारी तंत्र द्वारा नौकरी के बजाए लाठियों ने आग में घी का काम किया है। बड़ी संख्या में शिक्षित रोजगार उपलब्ध कराकर ही रोका जा सकता है। यहां ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि कोई भी राजनीतिक दल जो अपने चुनावी अभियान में बेरोजगारी दूर करने का सपना दिखाता है, वो सत्ता में आने के बाद अपना वायदा पूरा नहीं करता। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को मिल बैठकर इस भयावय समस्या के निदान के लिए एक नई आर्थिक नीति पर सहमत होना पड़ेगा। जिसके माध्यम से देश की सम्पदा, चंद हाथों तक सीमित होने के बजाय उसका विवेकपूर्ण बंटवारा हो। छोटे और मंझले उद्योगों के तेजी से बंद होने की मजबूरी को दूर करना होगा और इन उद्योगों को अविलंब पुनः स्थापित करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

घर में घिरे ट्रंप-लोकप्रियता व अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर लोकतांत्रिक देश के प्रमुखों को अपने देश पर दीर्घकालिक अवधि तक पद पर बने रहना है, तो उन्हें नेतृत्व के गुणों का धनी होना पड़ेगा,जिसमें त्वरित निर्णय, सबका साथ सबका विकास दुनियाँ को एक परिवार मानना, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि सहित कई मामलों में अमेंडिड, दृढ़ संकल्प, विश्वास के साथ सत्ता का संचालन करना होता है, अन्यथा सत्ता संभालने के कुछ महीनों में ही जनता का मोह भंग हो जाता है व धरने आंदोलन शुरू हो जाते हैं,इसका मकसद नागरिक अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह अहिंसात्मक आंदोलन कर अपनी जायज मांगों को रखना चाहते हैं,ताकि अन्याय कोसमाप्त किया जा सके। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं,क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अमेरिका में चल रही राजनीति का रिसर्च कर रहा हूं, अमेरिका में हम देख रहे हैं कि गुड ट्रबल लाइव्स बैनर तले चल रहा आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, दो दिन पूर्व मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के 50 राज्यों के 1600 से अधिक स्थानों पर यह आंदोलन चल रहा है, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव में किए गए वादों को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने की ओर कदम तीव्रता से बढ़ा रहे हैं,जो काबिले तारीफ है। परंतु मेरा मानना है कि उनके क्रियान्वयन व निर्णय में कुछ खामियां हो सकती है? उनके मुख्य मुद्दों में टैरिफ व इमीग्रेशन हैइमीग्रेशन पर अनेक राज्यों के अनेक नागरिक नाराज है, तो टैरिफ मुद्दे पर अब यूरोपीय यूनियन भी अच्छा खासा नाराज चल रहा है,व अपने स्तर पर आपस में साथियों कर अपनी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का खुद इंतजाम कर रहा है, जिसका सबसे सटीक उदाहरण अभी दो दिन पहले ब्रिटेन जर्मनी में समझौता हुआ व फ्रांस भी इनके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में अपनी पार्टी सहित, यूरोपीय यूनियन,व दुनियाँ के अनेक देशों में टैरिफ, इमीग्रेशन मुद्दों पर विरोध-लोग सड़कों पर उतरे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, गुड ट्रबल लाइव नामक विरोध आंदोलन,50 राज्यों के 1600 जगहों पर जबरदस्त आंदोलन,घर में घिरे ट्रंप- लोकप्रियता व अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट। साथियों बात अगर हम अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों की करें तो,अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनियाँ भर में ट्रेड और टैरिफ वार छेड़ने के साथ अपने कई अन्य अजीबोगरीब फैसलों के चलते अपने ही देश में घिर गए हैं। गत 2 दिनों से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के विभिन्न शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहेहैअमेरिकी जनता ट्रंप की कई नीतियों के विरोध में सड़क पर उतर आई है। पूरे देश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन और उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्टर, बैनर और नारों के साथ अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। गुड ट्रबल लाइव्स ऑन' नामक विरोध आंदोलन ने देश के सभी 50 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों को इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट भवन के पास एक चौराहे को अवरुद्ध करते हुए देखा गया। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारी एक इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए तो उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ "गुड ट्रबल लाइव्स ऑन" राष्ट्रीय विरोध दिवस के तहत तख्तियां थाम रखी थीं।ट्रंप के खिलाफ यह प्रदर्शन अटलांटा (जॉर्जिया), सेंट लुइस (मिसौरी), ओकलैंड (कैलिफोर्निया), और एनापोलिस (मैरीलैंड) समेत करीब 1600 जगहों पर हुआ। इसमें ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य देखभाल में कटौती, इमिग्रेशन नीतियों और अन्य फैसलों की खिलाफत की गई। इसका उद्देश्य दिवंगत कांग्रेस सदस्य और नागरिक अधिकारों के नेता जॉन लुईस को श्रद्धांजलि देना भी। साथियों बात अगर हम गुड ट्रबल लाइव्स ऑन आंदोलन को समझने की करें तो,गुड ट्रबल' आंदोलन का नाम जॉन लुईस की उस प्रसिद्ध अपील से लिया गया है, जो उन्होंने 2020 में अपनी मौत से पहले अमेरिकी नागरिकों से की थी। उन्होंने कहा था, "अच्छी परेशानी में पड़ो,जरूरी परेशानी में पड़ो और अमेरिका की आत्मा का उद्धार करो बता दें कि जॉन लुईस 'बिग सिक्स' नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह के अंतिम जीवित सदस्य थे, जिसका नेतृत्व डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। लुईस ने हमेशा अहिंसक आंदोलन और न्याय की लड़ाई का समर्थन किया, और यह आंदोलन उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाता है।पब्लिक सिटीजन संगठन की सह-अध्यक्ष लीसा गिल्बर्ट ने प्रदर्शन से पहले कहा, "हम अपने देश के इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में से एक से गुजर रहे हैं। प्रशासन में बढ़ते अधिनायकवाद और अव्यवस्था से हम सभी जूझ रहे हैं,जब हमारे लोकतंत्र के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और अपेक्षाओं को चुनौती दी जा रही है। इस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों और कार्यों के खिलाफ आवाज उठाना है जिन्हें कई नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। साथियों बात अगर हम ट्रंप के टैरिफ नीतियों पर बयानों को लेकर चर्चा होने की करें तो,बहरहाल, अपनी टैरिफ नीतियों पर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ट्रंप अमेरिका में कितने लोकप्रिय है, इससे जुड़ी एक सर्वे भी सामने आया है। इस खबर के मुताबिक देशवासी बीते छह महीनों की अवधि में ट्रंप की नीतियों को लेकर उतने खुश नहीं हैं। टैरिफ नीति के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। वहीं ट्रंप सरकार अपने बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती कर रही है और मेडिकेड सुविधा को भी कम कर रही है। इसके चलते अमेरिका में 1.1 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से बाहर हो जाएंगे। ट्रंप की नीतियों के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर हुए सर्वे के मुताबिक इस साल की शुरुआत में अप्रवासन के मुद्दे पर ट्रंप की जो रेटिंग थी, अब उसमें गिरावट आई है। इसके अलावा सरकारी खर्च में कटौती और मेडिकेड जैसे मुद्दों पर लोगों में भारी नाराजगी है।हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि राष्ट्रपति ट्रंप का एजेंडा जनता के बीच काफी हद तक अलोकप्रिय है।

एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश अमेरिकियों को लगता है कि उनके हस्ताक्षरित घरेलू नीति विधेयक से देश को नुकसान होगा, जेफरी एपस्टीन मामले की फाइलों को संभालने के उनके तरीके से वे असहमत हैं, और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को उनके अपने देश के अलावा अन्य देशों में निर्वासित करने का विरोध करते हैं। और सीएनएन/एसएसआरएस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकियों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा यह मानता है कि ट्रंप गलत प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिर भी, हालांकि राष्ट्रपति की कार्य स्वीकृति रेटिंग कम बनी हुई है, पिछले कई हफ्तों से यह अपेक्षाकृत स्थिर भी रही है।

दुनिया के सबसे चर्चित शख्स और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में चुनाव के बाद काफी कमी आई है अपनी नीतियों और बयानों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 30 जनवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालने वाले ट्रंप लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे लेकिन 5 महीना के उनके कार्यकाल के दौरान हुई फैसलों के कारण अमेरिकियों को अपनी नौकरी गवानी पड़ी और व्यापारियों को भी एक लंबा नुकसान हुआ है।यहां न्यूज नया गेम सर्वेक्षण के मुताबिक केवल 40 फीसदी अमेरिकी ही राष्ट्रपति ट्रंप को अभी भी पसंद करते हैं जबकि 56 प्रतिशत लोग खुले तौर पर उन्हें ना पसंद करते हैं। आपको बता दें यह सर्वेक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका में मई के महीने में निजी क्षेत्र में नौकरियों में कटौतियां हुई है पहले डोगे मिशन और उसके बाद ट्रंप की नीतियों का लोगों ने काफी विरोध किया है इसके अलावा ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल जा रहा है अभियान के तहत पूरे इन मामलों के विरोध में हजारों लोग सभी शहरों में सड़कों पर उतर आए थे इन लोगों को संभालने के लिए ट्रंप को सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी थी,ट्रंप की नीतियों के विरोध के चलते उनकी अप्रूव्ह रेटिंग भी उसे उनके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है अगर उनके पूर्व भर्ती राष्ट्रपतियों से तुलना करें तो ट्रंप का प्रदर्शनबराक ओबामा और जो बिडेन दोनों से ही खराब रहा है इन दोनों को ही अपने कार्यकाल के पांच महीनों बाद लोगों का बेहतर सपोर्ट मिला था,आपको बता दें मार्च के महीने में ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग लगभग 44 फीसद दी थी जो एक ही महीने में घटकर 40 पेर्सेंट पर आ गई है वहीं पहले केवल 50 पेर्सेंट प्रतिशत लोगों ने खुलकर नापसंद करते थे वहीं अब यह मात्रा 56 पेर्सेंट हो गई है। साथियों बात अगर हम यूरोपीय यूनियन देशों में अमेरिका के प्रति अविश्वास व आपसी समझौतों की करें तो, ब्रिटेन और जर्मनी ने गुरुवार (17 जुलाई, 2025) को एक व्यापक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे रक्षा से लेकर परिवहन तक के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा किया जा सके, जो चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज की पहली लंदन यात्रा को चिह्नित करता है, जो यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद करने के लिए नवीनतम यात्रा है।श्री मर्ज की यह एक दिवसीय यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ब्रिटेन की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद हो रही है, जो महाद्वीप के लिए खतरे तथा उनके अमेरिकी सहयोगी के बारे में अनिश्चितता के समय यूरोप की शीर्ष तीन शक्तियों के बीच अधिक सहयोग का संकेत है।हम रक्षा, विदेश नीति के क्षेत्र में, साथ ही आर्थिक और घरेलू नीति में भी अपने सहयोग को गहरा करना चाहते हैं। बर्लिन के एसडब्ल्यूपी थिंक-टैंक के निकोलाई वॉन ओंडार्जा ने कहा कि ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान करने के लगभग एक दशक बाद हुई यह संधि, एक ओर तो जर्मनी-ब्रिटिश संबंधों के सामान्य होने का संकेत है। दूसरी ओर, यह संधि इस बात का भी संकेत है कि ट्रान्सअटलांटिक अनिश्चितता के कारण ब्रिटेन एक सुरक्षा साझेदार के रूप में और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/00882)

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एच.एस.वी.पी. कार्यालयों की लापरवाही पर जताई कड़ी नाराज़गी

शिकायतकर्ता को 5 हजार मुआवज़ा देने के आदेश

चंडीगढ़ । हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक मामले में एस्टेट कार्यालय, कुरुक्षेत्र और जोनल प्रशासक, पंचकूला के बीच अनावश्यक देरी और अस्पष्ट प्रक्रिया को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया आयोग ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा संपत्ति हस्तांतरण के लिए 09 जून 2023 को दिया गया आवेदन लगभग दस महीने तक बार-बार तकनीकी और प्रशासनिक आधारों पर अस्वीकार किया जाता रहा । प्रवक्ता ने बताया जोनल प्रशासक कार्यालय द्वारा बार-बार की गई अस्वीकृतियां और देरी पूर्णतः अनुचित थीं और यह शिकायतकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न के समान है। आयोग ने इस मामले में 09 जून 2023 से 05 अप्रैल 2024 तक कार्यभार में रहे सभी जोनल प्रशासकों के खिलाफ अपनी कड़ी नाराज़गी दर्ज की है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(a) के अंतर्गत आयोग ने शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवज़ा देने के निर्देश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिए हैं। यह राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को प्रारंभ में स्वयं वहन करनी होगी और फिर संबंधित अधिकारियों से वसूली करनी होगी। आयोग ने एस.जी.आर.ए -सह-प्रशासक (मुख्यालय) के कार्यालय में भी गंभीर लापरवाही पाई, जहां एक ऑफलाइन अपील, जिसे भवन में ही बैठे अधिकारी को भेजा गया था, पंजीकृत डाक से भेजने के बाद लापता हो गई। आयोग ने इसे प्रशासनिक शिथिलता का गंभीर उदाहरण बताते हुए एस.जी.आर.ए द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया है। आयोग के अवर सचिव द्वारा 26 जून 2025 को संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट आयोग को 04 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की गई। निरीक्षण में यह सामने आया कि डाक प्राप्ति के रिकॉर्ड जैसे पियॉन बुक में जिम्मेदार अधिकारी का नाम स्पष्ट नहीं था। आयोग ने अंतिम आदेश में एच.एस.वी.पी. के सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया है कि पियॉन बुक, प्राप्ति रजिस्टर एवं प्रेषण रजिस्टर में जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा नाम व पदनाम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए अथवा पदनाम की मुहर लगाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जवाबदेही से बचा न जा सके।

हरियाणा के नव नियुक्त राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने सोमवार को राज्य के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

चंडीगढ़ ।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य जन रहे मौजूद

हरियाणा के नव नियुक्त राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने सोमवार को राज्य के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शील नागू ने प्रो. अशीम कुमार घोष को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अनुभवी राजनेता हैं, जो लगभग चार दशकों तक कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अकादमिक शोध और राजनीतिक विमर्श में सक्रिय योगदान सहित यूजीसी और आईसीएसएसआर परियोजनाओं पर भी काम किया है और उनके कई लेख प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनके अलावा, राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी सहित राज्यपाल के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, श्री महीपाल ढांडा, डॉ. अरविंद शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्री कृष्ण कुमार बेदी, श्रीमती श्रुति चौधरी, राज्य मंत्री श्री राजेश नागर और श्री गौरव गौतम, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, विधायकगण, विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्यपाल प्रो. अशीम कुमार घोष ने शपथ ग्रहण समारोह में आए महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी बधाई स्वीकार की। इस दौरान हरियाणा आर्म्ड पुलिस की स्पेशल टुकड़ी ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को साकार करने के लिए अंतरराज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का होगा आयोजन- गौरव गौतम'

चंडीगढ़ ।

'23 से 25 जुलाई तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम'

'तीन दिवसीय कार्यक्रम, 24 राज्यों के करीब 600 युवा लेंगे भाग, विभिन्न समुदायों की संस्कृति का होगा आदान प्रदान'

'2 अगस्त 2025 को खेल महाकुंभ की पंचकूला से होगी शुरुआत'

हरियाणा के खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता और कानून राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि भारत की विविधता में एकता सबसे बड़ी ताकत है। इसी कड़ी में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करने और सांस्कृतिक सदभावना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 23 से 25 जुलाई 2025 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतरराज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने यह बात आज यहां प्रैसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 24 राज्यों के करीब 600 युवा भाग लेंगे और जिसमें विभिन्न समुदायों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें ग्रुप फोग डांस, ग्रुप सांग, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि रहेंगी। खेल मंत्री श्री गौरव ने कहा कि 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं के लिए प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत बड़ा मंच होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू होगा। इस दौरान विभिन्न समुदायों के बीच एक, समानता और भाईचारे के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा समय में हरियाणा की कला एवं संस्कृति और खेलों के प्रभाव से अन्य कई राज्य प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उदेदश्य राष्ट्र निर्माण व सदभाव के लिए प्रतिबद्ध सशक्त युवा तैयार करने का संकल्प लिया हैं। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व, विकास, नेतृत्व क्षमता का निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर है। खेल मंत्री ने कहा कि 2 अगस्त 2025 को खेल महाकुंभ की शुरुआत पंचकूला से होगी। इस खेल आयोजन में विभिन्न इवेंट में खिलाड़ी अपना दमखम व कौशल दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1500 से ज्यादा खेल नर्सरियां खोली गई हैं। सरकार का हर साल 500 खेल नर्सरियां बनाने का लक्ष्य है। एक सवाल के जवाब में खेल मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और पुलिस अपराधियों से सख्ती से निपट रही है।

नई दिल्ली संसद भवन परिसर SIR की आड़ में बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ आज संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ।वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, हम इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। संविधान विरोधी शक्तियों के खिलाफ एकजुटता से लड़ेंगे। छाया- इंद्रजीत सिंह

कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव राजगढ़ डोभी को विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात

चंडीगढ़ । हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विकास और व्यवस्था की नई गाथा लिखी गई है। विकास परियोजनाओं का लाभ अब प्रदेश के सभी इलाकों और कोने कोने तक निष्पक्ष तरीके से बराबर पहुँच रहा है। जनकल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ गरीब परिवार के घर की दहलीज तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित बजट का एक - एक पैसा पारदर्शिता के साथ खर्च किया जा रहा है।

अधिकारियों की निष्ठा और लगन से समाधान शिविर के प्रति लोगों का बढ़ रहा विश्वासः उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया

पानीपत।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल मार्ग दर्शन का लाभ प्रदेश के नागरिकों को जनता समाधान शिविर के माध्यम से लगातार मिल रहा है। जिले व उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे इन समाधान शिविरों में ग्रामीण व शहरी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते है व अधिकारियों के सहयोग से उनका समाधान करवाते है। जिला सचिवालय में सोमवार के दिन समाधान शिविर में जरूरतमंदो की समस्याओं की सुनवाई करते हुए उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने कहा कि अधिकारियों की लगन और निष्ठा पर लोगों का अटूट विश्वास है। इसी विश्वास के तहत लोग दूर दराज से अपनी समस्याओं का निदान करवाने के लिए समाधान शिविर में पहुंचते है। इसे हर हाल में कायम रखना है। उपायुक्त ने कहा कि सप्ताह में दो दिन लगने वाले समाधान शिविर में उन लोगों को विशेष राहत मिल रही है जो लोग समस्याओं से ग्रस्त थे व समाधान की तालाश में कार्यालयों के बार - बार चक्कर लगा रहे थे उन लोगों को मुख्यमंत्री नायब सिंह के कुशल मार्ग दर्शन का लाभ मिल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आम तौर पर पैंशन विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है। इन समस्याओं का समाधान अधिकारी मौके पर करने का प्रयास करते है। इसमें एक व्यवस्था के तहत आम व्यक्ति की पैंशन संबंधी, फैमली आईडी संबंधी समस्याओं का समाधान मुख्य तौर पर किया जाता है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग का पहला कार्य

समाधान शिविर में आने वाली नागरिकों की समस्याओं का रुचि लेकर समाधान करना। जिस तरह के मामले समाधान शिविर में जनता द्वारा प्रस्तुत किए जाते है। उसमें अधिकारियों की बड़ी ताकत लगती है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। जनता का समाधान शिविरों के प्रति बढ़ता विश्वास सरकार व प्रशासन की छवि को और मजबूत कर रहा है। समाधान शिविर में अन्य दिनों की तरह सोमवार को भी पुलिस विभाग पेंशन विभाग व क्रीड विभाग से जुड़ी 72 समस्याएं पहुंची। उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया ने अधिकारियों के सहयोग से यात्रा का मुख्य प्रश्न आदान करने का प्रयास किया । समाधान शिविर में जाट सभा द्वारा डाहर गांव की 10 कैनल पंचायती भूमि सरकारी नियमानुसार दान व पट्टे पर देने का अनुरोध किया गया ताकि उस स्थान पर कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी, किसान विश्राम गृह और किसान विश्राम केंद्र बनाया जा सके। उपाय इतने इस मामले को गंभीरता से हल करने की निर्देश दिए। प्रार्थी धर्मशील ने उपायुक्त को अपने खेत की स्थिति बताई व कहा की किस तरह से फैक्ट्री व गोदाम का गंदा पानी उनकी फसल को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से गंदे पानी की निकासी की मांग भी रखी। प्रार्थी तनु रानी व रामकरण ने प्रशासन से दिव्यांग पेंशन बनवाने का अनुरोध किया। उपायुक्त ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रार्थी छोटी वासी नौल्था ने राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। उपायुक्त ने डीएफएससी नीतू को जांच कराने के निर्देश दिए। प्रार्थी साहिल वासी प्रकाश नगर ने गली व नाली का निर्माण करवाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जांच की निर्देश दिए। इस मौके पर सीईओ डॉक्टर किरण, नगराधीश टीनू पोसवाल, डीडीपीओ राजेश शर्मा डिप्टी सीईओ कंचन लता, डिप्टी सीएमओ दिव्या साहनी, कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. राधे श्याम, एलडीएम राजकुमार, डीएफसी नीतू, डीपीओ परमिंदर कौर, आयुष विभाग के डॉ. संजय राजपाल, जिला पुलिस कैप्लेड अधिकारी सुरेश, संजीव शर्मा, जोगिंदर के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

असम (सक्षम भारत) कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी ने अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ गुवाहाटी मेंराजनीतिक मामलों की समिति, पीसीसी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, फ्रंटल संगठन प्रमुख और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। छाया –सक्षम भारत

एमसीडी कर्मियों के इलाज में नौ करोड़ की हेराफेरी, जांच समिति ने अस्पताल से 2020 से हुए पत्राचार की जानकारी मांगी

नई दिल्ली।

दिल्ली व नोएडा के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में एमसीडी कर्मचारियों के कैशलेस इलाज का भुगतान करने में 9 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में एमसीडी ने भी जांच समिति गठित कर दी है। अब एमसीडी यह पता लगा रही है कि इसमें किसी निगम कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका संदिग्ध तो नहीं है। इसके लिए जांच समिति की पहली बैठक 16 जुलाई को हुई थी। इसके बाद जांच समिति ने अस्पताल को 2020 से हुए डिजिटल और व्यक्तिगत के अलावा जो भी पत्र व्यवहार हुआ उसकी जानकारी मांगी है। इसके बाद जल्द ही दूसरी बैठक बुलाकर यह देखा जाएगा कि भुगतान में गड़बड़ी कहीं एमसीडी के स्तर पर तो नहीं हुई। वहीं, सूत्रों मुताबिक एमसीडी एक निजी अस्पताल के प्रकरण के बाद दूसरे निजी अस्पतालों को भी हुए भुगतान की जांच करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि हम फिलहाल हम जिस अस्पताल का मामला सामने आया उसी मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो 9 करोड़ रुपये का भुगतान एमसीडी द्वारा किया गया और वह

निजी खातों में गया उसमें कहीं एमसीडी के कर्मचारियों के साथ दूसरे अन्य अधिकारियों की कमी तो नहीं है। अधिकारी ने बताया कि जो भी अस्पताल हमारे कर्मियों के कैशलेस इलाज के लिए एमसीडी से जुड़े हुए है उन सभी अस्पताल प्रबंधन को हम संपर्क कर यह कह रहे है कि जो लेन देन से संबंधी जो भी अधिकारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं उनकी सेवा समाप्त करने और उनकी विश्वसनीयता के लिए एमसीडी को अधिकृत रूप से जानकारी देते रहें। उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 में एक निजी अस्पताल प्रबंधन ने 74.90 लाख रुपये भुगतान न करने के लिए एमसीडी को संपर्क किया था। जब अस्पताल के अधिकारी एमसीडी दफ्तर पहुंचे तो एमसीडी ने पूर्व में ही इसके भुगतान की सूचना अस्पताल को दी। जांच में पता चला कि जो बिल का भुगतान एमसीडी ने किया था वह अस्पताल के खाते में नहीं बल्कि निजी खातों में गया था। अस्पताल के पूर्व कर्मियों ने अधिकारिक ई-मेल के काम न करने पर निजी ई-मेल के जरिये भुगतान दूसरे खाते में करने को कहा था। इसके आधार पर एमसीडी ने भुगतान कर दिया। भुगतान की राशि नौ करोड़ से अधिक हो सकती है।

नई दिल्ली सुल्तानपुरी, जलेबी चौक, कावड़ शिविर, क्षेत्रीय निगम पार्षद, दौलत पवार और जन जागृति युवा एकता एवं समाज कल्याण समिति के द्वारा शिव भक्त कावड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, वार्ड 44, के, निगम पार्षद, दौलत पवार व समिति के पदाधिकारियों ने पटका पहनकर विनय कुमार भारती, वसीम खान, प्रदीप कुमार मासु, अजहर सम्मानित किया. छायाः साहिल भारती

राज्यसभा से बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 पारित, जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए दिया गया नोटिस

नई दिल्ली । संसद में मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर चर्चा के लिए अड़ा है। वहीं सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस पर कहा, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक न्यायाधीश का आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने इस संबंध में अपना नोटिस दायर कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में राज्यसभा के 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का नोटिस दिया है। वहीं लोकसभा में भी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसे 145 सदस्यों ने समर्थन दिया है। सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जन सेना पार्टी, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, सीपीएम आदि के सांसद शामिल हैं। इन सांसदों में राहुल गांधी, अनुराग वर्मा, रवि शंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल है।

विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए : प्रियंका

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर वे (सरकार) चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए.

राहुल गांधी बोले- विपक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं

मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो विपक्ष का नेता हूं, को बोलने की अनुमति नहीं है। यह एक नया दृष्टिकोण है। परंपरा कहती है कि अगर सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्षी नेता नारेबाजी कर के सदन का वक्त बर्बाद न करें और चर्चा करें।

2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस- सभी 12 आरोपी बरी

हाईकोर्ट बोला- सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम; घटना में 189 लोग मारे गए थे

मुंबई । मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वान्टेड नहीं है, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन ट्रेनों के सात कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद यह फैसला आया है। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6 बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजकर 35 मिनट के बीच एक के बाद एक सात ब्लास्ट हुए थे। ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट में करवाए गए थे। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा-भायंदर रेलवे स्टेशनों के पास ये ब्लास्ट हुए थे। ट्रेनों में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बनाए गए थे, जिसे सात प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था।

बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान ढाका में स्कूल पर गिरा 16 छात्र, 2 शिक्षक और पायलट की मौत

171 घायल; 25 छात्रों की हालत गंभीर

ढाका ।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे बांग्लादेशी एयरफोर्स का ट्रेनिंग विमान माइलस्टोन कॉलेज की इमारत से टकरा गया. हादसे में 16 छात्रों की मौत हुई और कई घायल हुए हैं. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए है. प्लेन क्रैश की जानकारी मिलने के बाद बांग्लादेशी सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. हादसे में घायल हुए लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में माइलस्टोन कॉलेज कैंपस से धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है. कॉलेज के छात्र भी भागते हुए दिख रहे हैं. मौजूदा जानकारी के मुताबिक एफ-7 ट्रेनिंग विमान ने दोपहर करीब 1.06 बजे उड़ान भरी थी और 24 मिनट बाद 1.30 मिनट पर क्रैश हो गया. हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक सीनियर अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है. हालांकि अभी तक दुर्घटना का कारण पता नहीं चल सका है. प्लेन क्रैश की वजह से घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एफ-7 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसे चीनी कंपनी चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है. यह सिंगल सीटर विमान है. हालांकि इसके कुछ संस्करणों में डबल सीट का विकल्प भी मिलता है. एफ-7 की अधिकतम स्पीड मैक 2.02 यानी कि लगभग 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की है.

सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी, करणी सेना के योगेंद्र पर केस, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

मुरादाबाद ।

कैराना लोकसभा सीट की सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले योगेंद्र सिंह राणा पर कटघर थाने में केस दर्ज किया गया है। खुद को करणी नेता का नेता बताने वाले योगेंद्र सिंह राणा पर पुलिस ने सुनीता सिंह नाम की महिला की तहरीर पर कार्रवाई की है। सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एसपी सिटी से मुलाकात की थी।

इस दौरान सपा नेत्री सुनीता सिंह ने तहरीर दी थी। इसमें सुनीता सिंह ने बताया कि योगेंद्र सिंह राणा ने इस तरह की टिप्पणी कर एक महिला सांसद को सार्वजनिक रूप अपमानित किया है। यह उनकी गरिमा के खिलाफ है। योगेंद्र ने समाज की मूल संवैधानिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। कटघर थाने में खुद को करणी सेना का

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले योगेंद्र राणा ने रविवार को फिर से अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट साझा की। जिसमें उसने टिप्पणी को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। एसपी सिटी कुमार रण सिंह ने बताया कि योगेंद्र राणा के खिलाफ बीएनएस की धारा 79,356 (2) 67 आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है।

मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम एमके स्टालिन को आया चक्कर, अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के एक बुलेटिन के अनुसार, सुबह की नियमित सैर के दौरान उन्हें हल्का चक्कर आया। अपोलो अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं के निदेशक डॉ. अनिल बीजी ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री की वर्तमान में जाँच की जा रही है और सभी आवश्यक नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। अस्पताल ने एक बयान में कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सुबह की सैर के दौरान हल्का चक्कर आया। उनके लक्षणों की जाँच के लिए उन्हें चेन्नई के ग्रीम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक जाँचें की जा रही हैं। इस बीच, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पूर्व मंत्री और सांसद ए अनवर राजा सोमवार को चेन्नई अन्ना अरिवालयम में डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में शामिल हो गए। सोमवार को जब वह डीएमके मुख्यालय, अन्ना अरिवालयम पहुँचे, तो एआईएडीएमके ने उन्हें फिर से पार्टी से निष्कासित कर दिया।

हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को लताड़; कर्नाटक सीएम की पत्नी को दी राहत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जमकर लताड़ लगाई और ईडी के कथित राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने को लेकर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सीएम की पत्नी के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस पर खुशी जताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ और मुडा मामले का भी अंत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सीएम की पत्नी पार्वती के खिलाफ मुडा घोटाले में कार्रवाई करने पर रोक

लगा दी थी। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि श्रीमान राजू, कृपया हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। वर्ना हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से, मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है। इसे पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए, उसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

कर्नाटक सीएम ने जताई फैसले पर खुशी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और एक बयान जारी कर कहा कि आखिरकार न्याय हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ईडी के खिलाफ टिप्पणी करने में सावधानी बरती और उन्होंने कहा कि मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय के फैसले में कोई गलती नहीं लगी। न्याय हुआ और मुडा घोटाले में ईडी का दखल अब बंद हो जाएगा।

सीएम सैनी ने सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण को लेकर की बैठक

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री आज यहां प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही मोबाइल ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग अपनी सभी सड़कों को शत-प्रतिशत चिह्नित कर जल्द से जल्द ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाइल ऐप सरल होनी चाहिए ताकि आमजन उसका आसानी से उपयोग कर सकें। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे, इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

***अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता से सुदृढ़ करने के दिए निर्देश**

***सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्ता से किया जाए पूर्ण**

बड़ा हादसा टला, मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान, फट गए टायर; इंजन को भी नुकसान

नई दिल्ली ।

एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 2744 ए320 (वीटी-टीवाईए) सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी और शहर में भारी बारिश के कारण रनवे से आगे निकल गई। यह उड़ान केरल के कोच्चि से मुंबई आ रही थी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, खराब मौसम के कारण विमान लैंडिंग के तुरंत बाद रनवे से उतर गया। सूत्रों का कहना है कि लैंडिंग के दौरान विमान के तीन टायर फट गए और विमान का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया होगा। फिर भी, विमान सुरक्षित रूप से टर्मिनल गेट तक पहुंच गया, जहां सभी यात्री और चालक दल के सदस्य बिना किसी घटना के उतर गए। विमान सुबह लगभग 9.27 बजे

उतरा, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत सक्रिय हो गए। एयर इंडिया ने कहा कि घटना के बाद विमान को सुरक्षित रूप से गेट तक पहुंचा दिया गया। यह भी कहा गया कि विमान में सवार सभी यात्रियों और चालक दल को उतार दिया गया और विमान को जाँच के लिए रोक दिया गया। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, 21 जुलाई 2025 को कोच्चि से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली उड़ान संख्या एआई2744 में लैंडिंग के दौरान भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप लैंडिंग के बाद रनवे का रुख बदल गया। प्रवक्ता ने कहा, विमान सुरक्षित रूप से गेट तक पहुँच गया और सभी यात्री और चालक दल के सदस्य उतर चुके हैं। एयरलाइन ने आगे कहा, विमान को जाँच के लिए रोक दिया गया है।

घटना के समय विमान में सवार यात्रियों की संख्या तुरंत ज्ञात नहीं हो पाई। घटना के तुरंत बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) ने कहा कि, कोच्चि से आ रहा एक विमान 21 जुलाई 2025 को सुबह 9.27 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए), मुंबई के रनवे से बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि सीएसएमआईए की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को रनवे से बाहर निकलने की स्थिति को संभालने के लिए तुरंत सक्रिय कर दिया गया। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।